Rad&tion Leakage from Kota Nuclear Power Plant

344. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been radiation leakage from the Kota Nuclear Plant having serious effects on the inhabitants of the adjoining villages;

(b) if so, whether Government have made any detailed analysis of the radiation and its effects;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what measures have been taken by Government to check the radiation leakage to prevent serious health hazards on the inhabitants of the neighbouring villages?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) -No, Sir.

(b) and (c) Releases to the environment from Kota or any other nuclear power plant in the country are regulated by the limits prescribed by Atomic Energy Regulatory Board (AERB) and complied with by the operating stations. Such limits are in line with the guidelines stipulated by international bodies like International Commission on Radiological ftotection (ICRP). Radiation dose due to releases from Kota plant forms only a small percentage of the radiation dose due to the unavoidable natural background radiation.

(d) Environmental Survey Laboratories (ESL) are set up at all operating nuclear power stations including the Kota plant to monitor samples of water, soil, food, air and various other produce for radioactivity contents on a periodic basis. ESLs start functioning prior to start of nuclear power station operation to establish base . line data for future comparison. The finding of ESLs are reviewed by AERB. The existing regulatory framework provides for continuous review in safety and environmental aspects relating to nuclear power plants.

345. *(Transferred* to 26 *July,* 1991.)

346. *(Transferred* to 24 *July,* 1991).

Report of Bureau of Industrial Costand Pricing on Selling Price ofParaxylene

347. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Bureau of Industrial Cost and Pricing has submitted its report on the fair selling price of indigenous paraxylene;

(b) if so, what decision has been taken by Government in the matter; and

(c) what is Government's decision on refixation of the fair selling price of paraxylene produced by IPCL?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) and (b) The BICP has not examined the fair selling price of paraxylene produced by all indigenous manufacturers.

(c) There is no price control in the petrochemicals sector, and as such the question of fixing prices does not arise.H

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

348. श्री प्रजीत जोगी :
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पुनर्वासित किए गए भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके परिवारों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह पुनर्वास कृषि, उद्योग अथवा अन्य किसी क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पुनर्वासित किए गए ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है ; और

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों से संबंधित समूचे देश में आंकड़े क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास मुख्यत: रोजगार के क्षेत्र में किया गया है । मध्य प्रदेश में वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान क्रमश: 580, 540 और 421 भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास उपलब्ध कराया गया। (इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उपलब्ध किए गए पुनर्वास के आंकड़े भी शामिल हैं।) उपर्युक्त व्यवस्था के अलावा, भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार के लिए दो महत्वपूर्ण पुनर्वास योजनायें चलाई गई हैं :—

(1) भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार-1 (सेमफैक्स-1) जिसमें भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों को छोटे पैमाने के औद्योगिक यूनिटों की स्थापना करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है और (2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार-2 (सेमफैक्स-2) जिसके अंतर्गत खेती और खेती से बाहर के क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें सहायता प्रदान की जाती है । मध्य प्रदेश में, सेमफैक्स-1 योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ किए जाने की तारीख (अर्थात् अप्रैल, 1987 से दिसम्बर, 1990) तक 120 भूतपूर्व सैनिकों को ऋण दिया गया । सेमफैक्स-2 योजना के अंतर्गत योजना प्रारम्भ किए जाने की तारीख अर्थात जनवरी, 1988 से मार्च, 1991 तक 22 भूतपूर्व सैनिकों को ऋण प्रदान किया गया ।

(घ) इस संबंध में पूरे देश से संबंधित सूचना इस प्रकार है :—

	1988	1989	1990
पुनर्वास	21,872	18,853	15,909
सेमफैक्स-1 अप्रैल, 1987 से दिसम्बर 1990 तक			4001
सेमफैक्स-2 जनवरी, 1988 से मार्च 1991 तक			1214

राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की अन्य पुनर्वास योजनायें चलाई जा रही हैं जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं । इन योजनाओं में ये शामिल हैं :

औद्योगिक भू-खंडों के आवंटन में आरक्षण, परिवहन मार्ग के परमिट, आवास-स्थल, कृषि भूमि, दुग्ध केन्द्र, सब्जियों की दुकानें, जय जवान स्टालें आदि । इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निगरानी रखी जाती है ।

मारुति कारों का निर्यात

349. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कारों के निर्यात में हाल ही में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में मारुति कारों के निर्यात का ब्यौरा क्या है ; और